

केन्द्रीय आम बजट : 2020-21

वित्त मंत्री निर्मला सीमरमण ने 1 फरवरी, 2020 को लोक सभा में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट पेश किया। उन्होंने बजट को प्रौद्योगिकी और युवा वर्ग के विकास पर केन्द्रीत बताया। इस बजट के तीन प्रमुख भाग हैं- पहला, अकांक्षी भारत यानी शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान, दूसरा-सबके लिए आर्थिक विकास एवं तीसरा-संरक्षित समाज।

केन्द्रीय बजट : 2020-21

➤ व्यक्तिगत आयकर की एक नई व्यवस्था

- 5 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा।
- 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय पर 10 प्रतिशत और 7.5 से 10 लाख तक की वार्षिक आय पर 15 प्रतिशत की दर लागू होगी।
- 10 लाख से 12.5 लाख तक की वार्षिक आय पर 20 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।
- 12.5 लाख से 15 लाख तक आमदनी पर 25 प्रतिशत और 15 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30 प्रतिशत की दर से कर देना होगा।
- नई टैक्स व्यवस्था के तहत इसमें कोई डिडक्शन शामिल नहीं होगा, जो डिडक्शन लेना चाहते हैं वॉ पुरानी दरों से टैक्स दे सकते हैं।
- स्टार्टअप प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में रियायत दी गई है।
- करारोबार की सीमा 25 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ की गई है।

➤ शिक्षा और कौशल विकास

- 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं।
- शहरी स्थानीय निकाय युवा इंजीनियरों के लिए एक वर्ष तक का इंटरशिप उपलब्ध कराए जायेंगे।
- शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए वाणिज्यिक ऋण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाएगी। देश में 100 शीर्ष संस्थानों द्वारा डिग्री सतर का ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाएगा।
- 2030 तक भारत के पास विश्व की कार्यशील आयुवर्ग की सबसे बड़ी आबादी होगी।
- भारत उच्च शिक्षा के लिए पसंदीदा गंतव्य होना चाहिए और इसके लिए स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत एशियाई और अफ्रीकी देशों में इन्ड-सेट आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसका उपयोग उन विदेशी उम्मीदवारों की बेंचमार्किंग के लिए किया जायेगा जिन्हें भारत के उच्चतर शिक्षा केन्द्रों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ मिलती हैं।
- पुलिस विज्ञान, न्यायिक विज्ञान और साइबर न्यायिक विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का भी प्रस्ताव है।
- योग चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए PPP माध्यम से मौजूदा जिला अस्पतालों के साथ मेडिकल कॉलेजों को जोड़ा जायेगा।

➤ स्वास्थ्य एवं पोषण

- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में 69000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया

गया है जिसमें प्रधानमंत्री जन अरोग्य योजना के लिए 6400 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

- मिशन इन्द्रधनुष के तहत पांच नये टीकों सहित 12 बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए काम किया जा रहा है।
- फिट इंडिया अभियान जीवन शैली से उत्पन्न होने वाली गैर संचारी बीमारियों का मुकाबला करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 20 हजार से अधिक अस्पतालों को पैनलबद्ध किया गया है तथा छोटे शहरों में गरीबों के लिए और अधिक अस्पतालों की जरूरत है। PPP मॉडल के तहत अस्पतालों की स्थापना का भी प्रस्ताव है।
- 'टीवी हारेगा, देश जीतेगा' अभियान के तहत 2025 तक देश से टीबी को समाप्त करने के लिए सरकार गंभीरता से प्रयास करेगी।
- सस्ती दरों पर दवाईयाँ उपलब्ध कराने के लिए देश के सभी जिलों में जन औषधि केंद्र के विस्तार का प्रस्ताव है।
- जन औषधि केन्द्र योजना के तहत 2024 तक सभी जिलों में 1000 केन्द्र स्थापित करके 2000 औषधियों तथा 300 सर्जिकल सामान की उपलब्धता का प्रस्ताव है।
- इस वर्ष पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35600 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
- महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 28600 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

➤ बुनियादी ढांचे में सुधार

- सरकार के विकास कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्राथमिकता पर चर्चा करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि अभिनव और विश्व स्तरीय कार्यों से इन क्षेत्र में निधियों के प्रवाह में सुधार किया जायेगा।
- नवगठित केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के समग्र विकास में सरकार हरसंभव सहायता प्रदान करेगी।
- इस बजट में जम्मू कश्मीर के लिए 30757 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख के विकास के लिए 5958 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

➤ कृषि और किसान कल्याण

- सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, ग्रामीण सड़क योजना जैसे कार्यक्रमों से किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6 करोड़ 11 लाख किसानों के जीवन में खुशहाली आई है। कृषि सिंचाई योजना के जरिए दलहनी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।
- वित्तमंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए जो अन्य घोषणाएँ की हैं, उनमें प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाना भी शामिल है।
- जल्द खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के शीघ्रता से परिवहन के लिए विशेष 'किसान रेल' और 'किसान उड़ान' योजना शुरू करने का एलान किया गया है।
- प्रधानमंत्री KUSUM (किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान)

योजना के अंतर्गत बिजली ग्रिड से नहीं जुड़े सौर पम्पों को बढ़ावा देने की योजना के तहत 20 लाख किसानों को शामिल किया जाएगा।

- 2025 तक दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता में बढ़ोतरी का कार्यक्रम बनाया है।
- मछली पालन में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी वित्तमंत्री ने बजट में घोषणाएँ की हैं।

➤ महिला एवं बाल विकास

- नवजात बच्चों के लिए नई नीति लाई जायेगी। 35,000 करोड़ पोषण नीति के लिए तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 33,000 करोड़ आवंटित किए गये हैं।
- 10 करोड़ परिवारों को न्यूट्रिशन की जानकारी दी जायेगी।
- 6 लाख से अधिक आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिया जायेगा।

➤ रक्षा बजट

- बजट 2020 में रक्षा बजट में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। यह अब 3.37 लाख करोड़ हो गया है। पिछले साल तक यह 3.18 लाख करोड़ रुपये था। रक्षा क्षेत्र में दी जाने वाली पेंशन को जोड़ ले तो यह 4.7 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
- इस बार रक्षा क्षेत्र का पेंशन बजट 1.33 लाख करोड़ रुपये है। हथियारों की खरीद और आधुनिकरण के लिए 1,10,734 करोड़ दिए गये हैं।

➤ रेलवे बजट

- केंद्रीय बजट में रेलवे को 70,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता आवंटित की गई है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे के लिए कुल 1.61 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है।
- जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों के लिए राष्ट्रीय शीत आपूर्ति शृंखला के विकास की योजना के तहत निजी सरकारी भागीदारी (PPP) मॉडल में किसान रेल चलाएगी।
- सरकार का चुनिंदा मेल एक्सप्रेस और मालगाड़ियों के जरिए जल्द खराब होने वाले सामान की ढुलाई के लिए रेफ्रिजरेटेड पार्सल बैन का भी प्रस्ताव है।
- 24000 किमी. ट्रेन को इलेक्ट्रॉनिक बनाया जायेगा। तेजस ट्रेन की संख्या को बढ़ाया जायेगा।

➤ स्वच्छ भारत और जल जीवन मिशन

- 2020-21 के बजट में स्वच्छ भारत मिशन के लिए लगभग 12300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्त होकर ओडीएफ प्लस के प्रति वचनबद्ध है।
- सभी घरों को पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति के लिए 'जल जीवन मिशन' को 3.6 लाख करोड़ दिए गए हैं।
- जल संकट से जूझ रहे देश के 100 जिलों के लिए सरकार विस्तृत योजना लाएगी।

➤ सबके लिए मकान का लक्ष्य

- वित्तमंत्री ने सबके लिए सस्ते मकान का लक्ष्य हासिल करने के लिए आवास ऋण के ब्याज भुगतान पर मिलने वाली 3.5 लाख रुपये तक के टैक्स छूट को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है।
- देश में सस्ते आवास की आपूर्ति बढ़ाने के लिए टैक्स हॉलीडे का लाभ उठाने के वास्ते सस्ती आवास परियोजनाओं के अनुमोदन की तिथि में भी एक वर्ष की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है।

➤ गैर राजनीतिक पदों पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी

- इस बजट में अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए साझा योग्यता परीक्षा का प्रस्ताव किया गया है।
- इस पहल के तहत सरकार ने बजट में गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन परीक्षा करवाने के मकसद से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाने की घोषणा की गई है।

आम बजट 2020-21 : मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2020-21 के लिए अनुमातित प्राप्तियाँ 22.4 लाख करोड़ रुपये है। व्यय का संशोधित अनुमान 30.32 लाख करोड़ रुपये है। राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- 2019 में सरकार का ऋण घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 48.7 प्रतिशत हो गया है।
- निवेशकों को राहत देने के लिए लाभांश वितरण कर हटाने का प्रस्ताव है।
- कॉरपोरेट कर दर को 15 प्रतिशत के स्तर पर लाने का साहसी और ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।
- सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें मंजूर कर ली हैं।
- दो वर्ष में 60 लाख से अधिक करदाताओं को प्रक्रिया से जोड़ा गया है।
- भारत अभी विश्व की पांचवीं सभ्य बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- 2006 में 2016 के बीच भारत 271 मिलियन लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने में समर्थ था।
- बैंकों में जमा राशि पर बीमा सुरक्षा का दायरा एक लाख रुपये से बढ़ाकर पाँच लाख रुपये किया गया।
- राष्ट्रीय गैस ग्रिड का विस्तार कर इसे 27 हजार किलोमीटर करने की घोषणा की गयी है।
- 2024-25 तक मत्स्य निर्यात को एक लाख करोड़ रुपये तक पहुँचाना।
- 2022-23 तक देश में 200 लाख टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य।
- 3477 मित्रों और 500 मत्स्य पालन कृषक संगठनों द्वारा युवाओं को मत्स्य पालन क्षेत्र से जोड़ना।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना-गरीबी उन्मूलन के लिए 58 लाख एसएचजी के साथ 0.5 करोड़ परिवारों को जोड़ा गया।
- 2020-21 में ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 22000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
- आईकोनिक पर्यटन गंतव्य को जोड़ने के लिए तेजस जैसी ट्रेने।
- 2020-21 में भारतनेट कार्यक्रम के लिए 6000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे और दो अन्य पैकेज 2023 तक पूरे हो जाएंगे।
- चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेस-वे की शुरुआत होगी।
- पर्यटन संवर्द्धन के लिए वर्ष 2020-21 हेतु 2,500 करोड़ रुपये का आवंटन।
- वर्ष 2020-21 के लिए संस्कृति मंत्रालय हेतु 3,150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया है।
- भारत में 2022 में आयोजित होने वाले जी-20 की अध्यक्षता के लिए तैयारियां शुरू करने हेतु कुल 100 करोड़ रुपये आवंटित।
- आईआईएफसीएल तथा एनआईआईएफ जैसी अवसंरचना वित्त कंपनियों की सहायता के लिए 22000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे।
- सीमा शुल्क को फुटवियर पर 25% से बढ़ाकर 35% करने और फर्निचर वस्तुओं पर 20% से बढ़ाकर 25% करने का प्रावधान।
- न्यूज प्रिंट और हल्के कोटेट पेपर के आयात पर बुनियादी आयात शुल्क को 10% से घटाकर 5% किया गया।